



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2009/वैशाख 22, 1931

No. 271]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2009/VAISAKHA 22, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2009

सं. 50/2009-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 315(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 के साथ पठित, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है यथा :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :—

- (1) इन नियमों को भारत-सिंगापुर व्यापार करार (रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2009 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तित होंगे।

2. परिभाषाएँ :—

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो :—

(क) "महानिदेशक" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिनिर्धारण एवं मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले महानिदेशक (रक्षोपाय) से हैं।

(ख) "घरेलू उद्योग" से अभिप्राय,—

- (i) भारत में, पूरी तरह से एक जैसी वस्तु का समग्र रूप से या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु के उत्पादकों से है; या
- (ii) ऐसे उत्पादकों से है, जिनका, भारत में एक जैसी वस्तु या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु का सकल उत्पादन, भारत में उक्त वस्तु के सकल उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है।
- (ग) "वर्धित मात्रा" से अभिप्राय सिंगापुर गणराज्य से होने वाले आयात में हुई निरपेक्ष वृद्धि से है;
- (घ) "इच्छुक पार्टी" में शामिल है :—

- (i) सिंगापुर गणराज्य से कोई निर्यातक या उत्पादक या ऐसी वस्तुओं का आयातकर्त्ता जो रक्षोपाय उपायों को अपनाये जाने की दृष्टि से जांच के अधीन है या ऐसा व्यापारिक अथवा कारोबार संघ जिसके बहुसंख्यक सदस्य ऐसी वस्तु के उत्पादक, निर्यातक या आयातक हैं, या
- (ii) सिंगापुर गणराज्य की सरकार, या
- (iii) भारत में एक जैसी वस्तु या भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धात्मक वस्तु का उत्पाद या व्यापार अथवा कारोबार संघ जिसके बहुसंख्यक सदस्य एक जैसी वस्तु या भारत में प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्द्धात्मक वस्तु का उत्पादन या व्यापार करते हैं;
- (ड.) "गम्भीर क्षति" का अभिप्राय घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी भारी क्षति से है;
- (च) "गम्भीर क्षति का आशंका" से अभिप्राय ऐसे स्पष्ट व आसन्न खतरे से है जो कि तथ्यों पर आधारित हो न कि केवल अटकल या सुदूर संभावना पर आधारित हो;
- (छ) "एक जैसी वस्तु" से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जो जांच के अधीन माल के सभी मामलों में समान तथा एक जैसी है।
- (ज) "व्यापार करार" से अभिप्राय 'भारत गणराज्य और सिंगापुर गणराज्य के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार से है।"
- (2) ऐसे सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जिनका प्रयोग इन नियमों में तो हुआ है लेकिन वे परिभाषित नहीं किये गये हैं, का तात्पर्य वही होगा जो उनके लिये सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में दिया गया है।
3. महानिदेशक के कर्तव्य:-
- इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, महानिदेशक के कर्तव्य होंगे:-
- (i) व्यापार समझौते के तहत सीमा शुल्क में कटौती किये जाने या उसे हटाये जाने के कारण उत्पादित माल का निरपेक्ष रूप से अत्यधिक आयात किये जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका की जांच करना;
- (ii) ऐसी वस्तु को अभिज्ञात करना जो रक्षोपाय के प्रति जिम्मेदार है;
- (iii) व्यापार समझौते के अंतर्गत वरीय संव्यवहार के कारण माल के आयात में होने वाली वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका से संबंधित अपने निष्कर्ष, अनन्तिम या अन्यथा, को केन्द्र सरकार का प्रस्तुत करना;
- (iv) निम्न में से किसी के भी बारे में सिफारिश करना:-
- (क) व्यापार समझौते के अंतर्गत आने वाले माल पर सीमा शुल्क की किसी दर में और आगे की कटौती को निलम्बित रखना ।

(ख) ऐसे माल पर सीमा शुल्क दर को उस स्तर तक बढ़ाना जो उपाय किये जाने के वक्त ऐसी वस्तुओं पर लागू सीमा शुल्क की सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र दर या जांच की अवधि के शुरु होने के ठीक पहले दिन इन वस्तुओं पर लागू सीमा शुल्क की सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र की कमतर दर से अधिक न हो, अथवा

(ग) यदि ऐसे माल पर सीमा शुल्क की दर मौसमी आधार पर लागू होती है तो ऐसे मामले में सीमा शुल्क की दर उस स्तर तक बढ़ाना जो ऐसी जांच की अवधि के प्रारंभ के ठीक पहले तदनुरूपी मौसम के लिए माल पर लागू सीमा शुल्क की सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र कमतर दर से अधिक न हो ।

बशर्ते कि रक्षोपाय उपायों की प्रमात्रा और अवधि, यदि इनको लागू किया जाता है, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति या क्षति की आशंका करने के लिए पर्याप्त होगी ।

(v) रक्षोपाय उपायों को जारी रखने की आवश्यकता पर विचार करना ।

4. जांच की शुरुआत

(1) उपनियम (4) में किये गये प्रावधान को छोड़कर महानिदेशक, एक जैसी वस्तु के या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु के घरेलू उत्पादक के द्वारा या उसकी ओर से दिये गये लिखित आवेदन को प्राप्त करने पर ऐसी गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका के अस्तित्व का पता लगाने के लिए जांच शुरु करेंगे जो व्यापार समझौते के अंतर्गत वरीय संव्यवहार के कारण निरपेक्ष रूप से इस वस्तु के आयात में हुई वृद्धि के कारण हुई है।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत कोई भी आवेदन उस रूप में होगा जो महानिदेशक के द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है और ऐसे आवेदन के समर्थन में निम्नलिखित संलग्न होने चाहिए:-

(i) निम्नलिखित से संबंधित साक्ष्य:-

(क) बढ़ा हुआ आयात

(ख) घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका

(ग) व्यापार समझौते के अंतर्गत सीमा शुल्क दर में कटौती या निरसन जिसके कारण आयात में पर्याप्त वृद्धि होती है (कोई जरूरी नहीं कि यह किसी अन्य कारण के बराबर हो या उससे अधिक हो) और केवल ऐसी आयात वृद्धि से ही घरेलू उद्योग को गंभीर खतरा पैदा हो गया हो।

(ii) आयात प्रतिस्पर्धा में सकारात्मक समायोजन के लिए किये जा रहे या किये जाने के लिये नियोजित या दोनों ही, प्रयासों से संबंधित विवरण ।

(3) महानिदेशक उपनियम (1) के अंतर्गत दिये गये आवेदन के अनुसरण में तब तक कोई जांच कार्य शुरू नहीं करेंगे जब तक कि वे आवेदन में दिये गये साक्ष्यों की परिशुद्धता और पर्याप्तता की जांच नहीं कर लेते हैं और स्वयं इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त साक्ष्य हैं:-

- (i) बढ़ा हुआ आयात
- (ii) घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका
- (iii) व्यापार समझौते के अंतर्गत सीमा शुल्क दर में की गई कटौती या निरसन जिसके कारण आयात में पर्याप्त वृद्धि होती हो (कोई जरूरी नहीं कि यह किसी अन्य कारण के बराबर हो या उससे अधिक हो) और केवल ऐसी आयात वृद्धि से ही घरेलू उद्योग को गंभीर खतरा पैदा हो गया हो।

(4) उपनियम (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, महानिदेशक अपनी ओर से भी जांच शुरू करवा सकते हैं यदि वे सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत नियुक्त किसी सीमा शुल्क आयुक्त या अन्य किसी स्रोत से प्राप्त जानकारी के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि उपनियम (3) के खंड (i), खंड (ii) खंड (iii) में यथा संदर्भित, ऐसी जांच के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

5. जांच कार्य को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत

(1) महानिदेशक, व्यापार समझौते के अंतर्गत वरीय संव्यवहार के कारण भारत में किसी वस्तु के आयात में होने वाली वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका के निर्धारण के लिए जांच कार्य शुरू करने के बारे में निर्णय लेने के पश्चात् एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा जिसमें अपने निर्णय को अधिसूचित करेगा। इस सार्वजनिक नोटिस में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त जानकारी निहित होगी यथा:-

- (i) निहित वस्तु का संक्षिप्त वर्णन,
- (ii) जांच कार्य शुरू किये जाने की तारीख,
- (iii) तथ्यों का संक्षिप्त विवरण जिस पर गंभीर क्षति का आरोप अथवा गंभीर क्षति की आशंका आरोप आधारित है,
- (iv) जांच शुरू करने के कारण,
- (v) पता, जिस पर इच्छुक पक्षकारों द्वारा अभ्यावेदन प्रेषित किया जाए, और,
- (vi) इच्छुक पक्षकारों को उपर्युक्त अभ्यावेदन के जरिए अपने विचार व्यक्त करने के लिए अनुमत्य समय सीमा।

(2) सार्वजनिक सूचना की प्रति महानिदेशक द्वारा केन्द्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों, वस्तु, जिनके अत्यधिक आयात से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने अथवा क्षति पहुंचाने की आशंका का आरोप है, के ज्ञात निर्यातकों, सिंगापुर गणराज्य और अन्य इच्छुक पक्षकारों को प्रेषित किया जाएगा।

(3) महानिदेशक नियम 4 के उपनियम (1) में उल्लिखित आवेदन की एक प्रति भी निम्नलिखित को प्रदान करेंगे:-

- (i) प्रसिद्ध निर्यातक अथवा संबंधित व्यापार संघ,
- (ii) सिंगापुर गणराज्य की सरकार, और
- (iii) केन्द्र सरकार का वाणिज्य मंत्रालय

बशर्ते कि महानिदेशक किसी अन्य इच्छुक पक्षकार को भी उसके लिखित अनुरोध पर आवेदन की प्रति उपलब्ध कराएंगे।

(4) विषयगत वस्तु का आयात घरेलू विक्रय के दृष्टिकोण से बाजार के अंशदान के 2% से कम होने अथवा कुल आयात के 3% से कम होने पर जांच तत्काल बंद कर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण:- इस उपनियम के उद्देश्य के लिए:-

- (i) बाजार के अंशदान का अर्थ खंड (ii) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के दौरान कुल घरेलू उत्पाद जमा कुल आयात के मूल्य की प्रतिशतता के तौर पर सिंगापुर से आयात का मूल्य है; और,
- (ii) लागू प्रतिशतताओं के परिकलन में प्रयुक्त होने वाली समय सीमा याचिका दायर करने से बारह महीने पूर्व होगी।

(5) महानिदेशक नोटिस जारी कर सकते हैं जिसमें उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में कोई भी सूचना निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और इच्छुक पक्षकारों की सरकारों से मांगी जा सकती है और ऐसी सूचना ऐसे व्यक्तियों और सरकारों द्वारा लिखित नोटिस प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के अंदर अथवा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर महानिदेशक द्वारा बढ़ाई गई अवधि के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के उद्देश्य के लिए सार्वजनिक नोटिस एवं अन्य दस्तावेजों को महानिदेशक द्वारा पंजीकृत डाक से इन दस्तावेजों को भेजने अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित करने की तिथि के एक सप्ताह बाद प्राप्त किया गया माना जाएगा।

(6) महानिदेशक जांच के दौरान वस्तु के औद्योगिक उपभोक्ता को तथा ऐसे मामलों में जहां सामान्य तौर वस्तु का खुदरा स्तर पर विक्रय किया जाता है प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को भी जांच के लिए प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेंगे।

(7) महानिदेशक इच्छुक पक्षकार अथवा इसके प्रतिनिधि को मौखिक जांच के लिए महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं, परन्तु महानिदेशक ऐसी मौखिक सूचना पर विचार तभी करेंगे जब बाद में इसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) महानिदेशक इच्छुक पक्षकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को जांच में हिस्सा लेने वाले अन्य इच्छुक पक्षकारों को उपलब्ध कराएंगे।

(9) ऐसे मामले में जहां इच्छुक पक्षकार आवश्यक सूचना सुलभ कराने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के अंतर्गत सूचना नहीं प्रदान करता है अथवा जांच में अड़चन डालता है तो महानिदेशक अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों में वे जैसा उपयुक्त समझे केन्द्र सरकार के पास सिफारिश भेज सकते हैं।

6. गोपनीय सूचनाएं:-

(1) नियम 5 के उपनियम (1), (3) और (8), नियम 8 के उपनियम (2) और नियम 10 के उपनियम (5) में किसी बात के बावजूद, किसी भी सूचना को जो गोपनीय प्रकृति की है अथवा जिसे गोपनीय आधार पर प्रदान किया जाता है, कारण बताए जाने पर महानिदेशक द्वारा गोपनीय माना जाएगा और ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना वे इसे प्रकट नहीं करेंगे।

(2) महानिदेशक गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों से उसका गैर गोपनीय संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का संक्षिप्त विवरण नहीं दिया जा सकता है तो ऐसे पक्षकार को महानिदेशक के पास उन कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों संक्षिप्त विवरण संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में किसी भी बात के बावजूद, यदि महानिदेशक संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रदान करने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य अथवा संक्षिप्त रूप में इसे प्रकट करने का प्राधिकार देने का इच्छुक नहीं है तो वे ऐसी सूचना को तब तक के लिए नजर अंदाज कर सकते हैं जब तक कि वे उपयुक्त स्रोतों से संतुष्ट न हो जाएं कि ऐसी सूचना सही है।

7. गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की आशंका का निर्धारण

(1) महानिदेशक घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने अथवा गंभीर क्षति की आशंका का निर्धारण करेंगे और इसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ वस्तु के सभी प्रासंगिक कारकों और विशेष तौर पर उस उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाली परिमाणात्मक प्रकृति, निरपेक्ष दृष्टिकोण से संबंधित वस्तु के आयात में वृद्धि की दर और राशि, विक्रय, उत्पादन उत्पादकता, क्षमता उपयोग, मुनाफा और नुकसान तथा रोजगार के स्तर पर परिवर्तनों का ध्यान रखा जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर की गई जांच से यह पता नहीं चले कि केवल व्यापार करार के अंतर्गत आयात के वरीय संव्यवहार के कारण ही बढ़े हुए आयात से तथाकथित गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की आशंका पैदा हुई है। जब बढ़े हुए

आयात को छोड़कर अन्य कारक साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों तो ऐसी क्षति का कारण बढ़े हुए आयात को नहीं बताया जाएगा।

(3) इस नियम के अंतर्गत निर्धारण, कि मूल वस्तु का आयात व्यापार करार में प्रदान की गई सीमा शुल्क में कमी अथवा छूट के परिणामस्वरूप किया जा रहा है, तभी किया जा सकता है यदि ऐसी कमी अथवा छूट ऐसा कारण हो जिसका आयात की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान हो, परन्तु इसका अन्य कारण के बराबर होने अथवा बढ़ा होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आयात वृद्धि ऐसी कमी अथवा छूट से प्रकट रूप में संबंधित नहीं हो तो ऐसा निर्धारण नहीं किया जाएगा।

(4) ऐसी कटौती या निरसन की शुरुआत या समाप्ति के बीच की अवधि का बीतना और आयात में वृद्धि उपनियम (3) के अधीन निर्धारण को स्वतः नहीं रोकेंगे।

8. प्रारंभिक निष्कर्ष-

- (1) महानिदेशक शीघ्रता से जांच कार्य करेंगे तथा नाजुक स्थितियों में गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की आशंका के बारे में प्रारंभिक निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।
- (2) महानिदेशक अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में एक आम सूचना जारी करेंगे।
- (3) महानिदेशक आम सूचना की एक प्रति भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय को भेजेंगे।

9. अनंतिम रक्षोपाय उपायों का आवेदन पत्र-

यदि महानिदेशक अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में यह निर्धारित करते हैं कि व्यापार समझौते के अंतर्गत सीमा शुल्क में कटौती या निरसन के फलस्वरूप सिंगापुर गणराज्य में उद्भूत होने वाली कोई वस्तु इतनी बड़ी मात्रा में निरपेक्ष निबंधनों एवं ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार आयात की जा रही है कि अकेले सिंगापुर गणराज्य से ही ऐसी वस्तु के आयात से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका हो सकती है तो केन्द्र सरकार-

(i) व्यापार समझौते के अंतर्गत उस वस्तु पर उपलब्ध करायी गयी सीमा शुल्क की किसी दर में और कटौती को निलंबित कर सकती है: या

(ii) उस वस्तु पर सीमा शुल्क की दर को इतना बढ़ा सकती है जो निम्नलिखित से कम न हो,-

(क) उपाय करने के समय वस्तु पर लागू सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के सीमा शुल्क की दर से, और

(ख) जांच की अवधि शुरू होने के तत्काल पूर्ववर्ती तारीख को वस्तु पर लागू सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के सीमा शुल्क की दर से या,

(iii) किसी वस्तु पर मौसम के आधार पर सीमा शुल्क लगाए जाने के मामले में, सीमा शुल्क की दर को इतना बढ़ा सकती है जो जांच शुरू होने से

तत्काल पूर्व की तारीख को संगत मौसम में उस वस्तु पर लागू सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के सीमा शुल्क की कमतर दर से अधिक न हो:

बशर्ते कि ऐसे रक्षोपाय उपाय केवल ऐसी अवधि तक प्रभावी रहेंगे जो इसे अधिरोपित करने की तारीख से दो सौ दिनों से अधिक न हो।

10. अंतिम निष्कर्ष-

(1) महानिदेशक, जांच की शुरुआत होने की तारीख से आठ महीनों के भीतर, जिसे केन्द्र सरकार अधिकतम एक साल तक बढ़ा सकती है, निर्धारित करेंगे कि क्या,-

(i) जांच के अधीन की वस्तु ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचायी है या क्षति की आशंका पैदा की है; और

(ii) व्यापार समझौते के अंतर्गत वरीय संव्यवहार के कारण बढ़े हुए आयात और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका के बीच अस्थायी संबंध है।

(2) महानिदेशक भी रक्षोपायों के बारे में अपनी अनुशंसा देगा जो यदि लागू हों, तो गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने और सकारात्मक समायोजन करने के लिए पर्याप्त होंगे।

(3) महानिदेशक रक्षोपाय उपायों की अवधि के बारे में भी अपनी सिफारिशें देंगे।

बशर्ते, कि जहां अनुशंसित अवधि एक साल से अधिक होगी, महानिदेशक सकारात्मक समायोजन को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त प्रगामी उदारीकरण की भी सिफारिश करेंगे।

(4) अंतिम निष्कर्ष यदि सकारात्मक हुए, तो उसमें तथ्यों के बारे में तथा ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों के बारे में सभी सूचनाएं होगी।

(5) महानिदेशक अपने अंतिम निष्कर्षों को दर्ज करते हुए एक आम सूचना जारी करेंगे।

(6) महानिदेशक अपने अंतिम निष्कर्षों के बारे में आम सूचना की एक प्रति भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को भेजेंगे।

11. रक्षोपायों उपायों को लागू करना

महानिदेशक की सिफारिशें प्राप्त करने पर, केन्द्र सरकार गंभीर क्षति को रोकने या उसका उपचार करने तथा सकारात्मक समायोजन को सुकर बनाने के लिए अंतिम निष्कर्षों में शामिल वस्तु के संदर्भ में व्यापार समझौते के प्रावधानों को कारगर बनाने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना को समुचित रूप से संशोधित कर सकती है:

बशर्ते, कि यदि उस वस्तु के संबंध में कोई विश्वव्यापी रक्षोपाय लागू है तो उस वस्तु के विरुद्ध कोई रक्षोपाय उपाय नहीं किया जाएगा। किसी वस्तु विशेष के संबंध में कोई विश्वव्यापी रक्षोपाय उपाय करने के मामले में उस वस्तु के विरुद्ध

किया गया कोई द्विपक्षीय रक्षोपाय निरस्त हो जाएगा तथा रक्षोपाय के निरस्त हो जाने पर शुल्क की दर वह दर होगी जो इस कार्रवाई के पहले प्रवृत्त होती।

12. रक्षोपाय उपाय के प्रारंभ की तारीख

नियम 11 के तहत किए गए रक्षोपाय उपाय सरकारी गजट में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे जिसके द्वारा यह उपाय किए जाएंगा।

13. शुल्क की वापसी

यदि जांच के निष्कर्ष से पहले किए गए रक्षोपाय उपाय का परिणाम छूट का ऐसा स्तर होता है जो पहले ही किए गए अनंतिम रक्षोपाय उपाय से कम है, तो आयातक को शुल्क का अन्तर वापस कर दिया जाएगा।

14. अवधि

(1) नियम 12 के अंतर्गत किए गए रक्षोपाय उपाय केवल ऐसी अवधि के लिए होंगे जो गंभीर क्षति को रोकने या उसका उपचार करने तथा सकारात्मक समायोजन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक हों।

(2) इस नियम के उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए, नियम 12 के अंतर्गत लागू रक्षोपाय उपाय, जब तक पहले ही प्रतिसंहरित न किए जाएं, अपने लागू होने के दो साल बाद प्रभावी नहीं होंगे:

बशर्ते यदि केन्द्र सरकार का मत हो कि घरेलू उद्योग ने ऐसी क्षति या उसकी आशंका को समायोजित करने का उपाय कर लिया है तथा यह आवश्यक है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जारी रहना चाहिए, तो वह ऐसे अधिरोपण की अवधि एक साल तक बढ़ा सकती है।

(3) इस नियम के उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 12 के अंतर्गत किए गए रक्षोपाय उपाय, जब तक पहले ही प्रतिसंहरित न किए जाएं, अपने अधिरोपण की तारीख से 3 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएंगे।

15. समीक्षा

(1) महानिदेशक समय-समय पर रक्षोपाय उपाय का प्रयोग जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे और यदि वह अपने द्वारा प्राप्त सूचनाओं से संतुष्ट होंगे कि-

(i) गंभीर क्षति रोकने या उपचार करने के लिए रक्षोपाय उपाय जरूरी है तथा इस बात का प्रमाण है कि उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहे हैं तो वह केन्द्र सरकार से शुल्क का अधिरोपण जारी रखने की सिफारिश कर सकते हैं;

(ii) ऐसे उपाय का अधिरोपण जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है तो सरकार से इसे वापस लेने की सिफारिश करेंगे:

बशर्ते कि जहां रक्षोपाय उपाय लागू करने की अवधि एक वर्ष से अधिक होती है तो महानिदेशक स्थिति की समीक्षा करेंगे जो ऐसे अधिरोपण की मध्यावधि के बाद नहीं होगा, और यदि समुचित हो, तो ऐसे रक्षोपाय उपाय को वापस लेने अथवा उसमें समुलित संशोधन करने की सिफारिश करेंगे ।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रारंभ की गयी किसी समीक्षा का समापन ऐसी समीक्षा की शुरुआत होने की तारीख से 8 माह से अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर होगा, जिसकी केन्द्र सरकार अनुमति दे ।

(3) समीक्षा के मामले में नियम 4,5,6 और 10 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

[फा. सं. 467/06/2008-सीमा शुल्क-V]

सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th May, 2009

No. 50/2009-Customs (N.T.)

G.S.R. 315(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. -

- (1) These rules shall be called the India-Singapore Trade Agreement (Safeguard Measures) Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. -

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Director-General" means the Director-General (Safeguard) appointed by the Central Government under sub-rule (1) of rule 3 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997;
- (b) "Domestic industry" means the producers-
 - (i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or
 - (ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India;
- (c) "Increased quantity" means absolute increase in imports from the Republic of Singapore;
- (d) "Interested party" includes, -
 - (i) any exporter or producer from the Republic of Singapore or importer of the article subjected to investigation for purposes of taking safeguard measure or a trade or business association, majority of the members of which are producers, exporters or importers of such an article, or,
 - (ii) the Government of the Republic of Singapore, or,
 - (iii) a producer of the like article or directly competitive article in India or a trade or business association, a majority of members of which produce or trade the like article or directly competitive article in India;

- (e) "Serious injury" means a significant overall impairment in the position of the domestic industry;
- (f) "threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury on the basis of facts and not merely on allegation conjecture or remote possibility;
- (g) "Like article" means an article which is identical or alike in all respects to the goods under investigation;
- (h) "Trade Agreement" means the "Comprehensive Economic Co-operation Agreement between the Republic of India and the Republic of Singapore".

(2) All words and expressions used and not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

3. Duties of the Director-General. -

Subject to the provisions of these rules, it shall be the duty of the Director-General, -

- (i) to investigate the existence of serious injury or threat of serious injury to the domestic industry as a consequence of increased import of the originating goods in absolute terms, on account of reduction or elimination of a customs duty in terms of the Trade Agreement;
- (ii) to identify the article liable for safeguard measure;
- (iii) to submit his findings, provisional or otherwise, to the Central Government as to the serious injury or threat of serious injury to domestic industry consequent upon increased import of the goods due to preferential treatment under the Trade Agreement;
- (iv) to make recommendation for either, -
 - (a) suspending further reduction of any rate of customs duty on the goods provided for under the Trade Agreement, or,
 - (b) increasing the rate of customs duty on the goods to a level not to exceed the lesser of the Most Favoured Nation (MFN) applied rate of customs duty on the article in effect at the time the measure is taken, and, the Most Favoured Nation (MFN) applied rate of customs duty on the article in effect on the day immediately preceding the date of the start of the period of investigation, or,
 - (c) in a case of customs duty being applied to the goods on seasonal basis, increasing the rate of customs duty to a level not to exceed the lesser of the Most Favoured Nation (MFN) applied rate of customs duty that was in effect on the goods for the corresponding season immediately preceding the date of the start of the period of investigation:

Provided that the quantum and duration of safeguard measures, if applied, would be adequate to remove the injury or threat of injury to the domestic industry.

- (v) to review the need for continuance of safeguard measure.

4. Initiation of investigation. -

- (1) Except as provided in sub-rule (4), the Director-General shall, on receipt of a written application by or on behalf of the domestic producer of like article or directly competitive article, initiate an investigation to determine the existence of serious injury or threat of serious injury to the domestic industry, caused by increased import of an article in absolute terms due to preferential treatment under the Trade Agreement.
- (2) An application under sub-rule (1) shall be in the form as may be specified by the Director-General in this behalf and such application shall be supported by:-
- (i) evidence of -
 - (a) increased imports,
 - (b) serious injury or threat of serious injury to the domestic industry;
 - (c) the reduction or elimination of a customs duty under the Trade Agreement being a cause which contributes significantly to the increase in imports (but need not be equal to or greater than any other cause) and such increase in imports alone constitutes a substantial cause of serious injury to domestic industry.
 - (ii) a statement on the efforts being taken, or planned to be taken, or both, to make a positive adjustment to import competition.
- (3) The Director-General shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless he examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies himself that there is sufficient evidence regarding-
- (i) increased imports,
 - (ii) serious injury or threat of serious injury, and,
 - (iii) the reduction or elimination of a customs duty under the Trade Agreement being a cause which contributes significantly to the increase in imports (but need not be equal to or greater than any other cause) and such increase in imports alone constitutes a substantial cause of serious injury to domestic industry.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Director-General may initiate an investigation *suo motu* if he is satisfied with the information received from any Commissioner of Customs appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or any other source that sufficient evidence exists as referred to in clause (i), clause (ii) and clause (iii) of sub-rule (3).
5. Principles governing investigations. -
- (1) The Director-General shall, after he has decided to initiate investigation to determine the serious injury or threat of serious injury to domestic industry, consequent upon the increased import of an article into India on account of preferential treatment under the Trade Agreement, issue a public notice notifying his decision thereto. The public notice shall, *inter alia*, contain adequate information on the following namely:-
- (i) the precise description of the article involved,
 - (ii) the date of initiation of the investigation,

1770 GI/09-4

- (iii) a summary statement of the facts on which the allegation of serious injury or threat of serious injury is based,
 - (iv) reasons for initiation of the investigation,
 - (v) the address to which representations by interested parties should be directed, and,
 - (vi) the time-limits allowed to interested parties for making their views known through appropriate representation.
- (2) A copy of the public notice shall be forwarded by the Director-General to the Central Government in the Ministry of Commerce and other Ministries concerned, known exporters of the article the increased import of which has been alleged to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry, the government of the Republic of Singapore and other interested parties.
- (3) The Director-General shall also provide a copy of the application referred to in sub-rule (1) of rule 4 to:-
- (i) the known exporters, or the concerned trade associations,
 - (ii) the government of the Republic of Singapore, and
 - (iii) the Central Government in the Ministry of Commerce:

Provided that the Director-General shall also make available a copy of the application, upon request in writing, to any other interested party.

- (4) The investigation shall be promptly terminated if imports of the subject article represent less than 2% of market share in terms of domestic sales or less than 3% of the total imports.

Explanation: - For the purpose of the this sub-rule, -

- (i) market share means the value of the imports from Singapore as a percentage of value of total domestic production plus total imports during the time frame specified in clause (ii); and,
 - (ii) the time frame to be used in calculating the applicable percentages shall be the twelve months prior to the filing of the petition.
- (5) The Director-General may issue a notice, calling for any information in such form as may be specified by him from the exporters, foreign producers and governments of interested countries and such information shall be furnished by such persons and governments in writing within thirty days from the date of receipt of the notice or within such extended period as the Director-General may allow on sufficient cause being shown.

Explanation: For the purpose of this rule, the public notice and other documents shall be deemed to have been received one week after the date on which these documents were sent by the Director-General by registered post or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country.

- (6) The Director-General shall also provide opportunity to the industrial user of the article under investigation and to representative consumer organisations in cases where the article is commonly sold at retail level to furnish information which is relevant to the investigation.

- (7) The Director-General may allow an interested party or its representative to present the information relevant to investigation orally but such oral information shall be taken into consideration by the Director-General only when it is subsequently submitted in writing.
- (8) The Director-General shall make available the evidence presented to him by one interested party to the other interested parties, participating in the investigation.
- (9) In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, the Director-General may record his findings on the basis of the facts available to him and make such recommendations to the Central Government as he deems fit under such circumstances.

6. Confidential information. -

- (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (3) and (8) of rule 5, sub-rule (2) of rule 8 and sub-rule (5) of rule 10, any information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis shall, upon cause being shown, be treated as such by the Director-General and shall not be disclosed without specific authorisation of the party providing such information.
- (2) The Director-General may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of the party providing such information, such information cannot be summarised, such party may submit to the Director-General a statement of reasons why summarisation is not possible.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the Director-General is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is unwilling either to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, he may disregard such information unless it is demonstrated to his satisfaction from appropriate sources that such information is correct.

7. Determination of serious injury or threat of serious injury. -

- (1) The Director-General shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, *inter alia*, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment.
- (2) The determination under sub-rule (1) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, that the increased imports due to preferential treatment of imports under the Trade Agreement alone constitute the substantial cause of the alleged serious injury or threat of serious injury. When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports.
- (3) The determination under this rule, that the originating article is being imported as a result of the reduction or elimination of a customs duty provided for in the Trade Agreement, shall be made only, if such reduction or elimination is a cause which contributes significantly to the increase in imports, but need not be equal to or greater than any other cause. If the increase in imports is demonstrably unrelated to such reduction or elimination, such determination shall not be made.

1770 GI/08-5

- (4) The passage of a period of time between the commencement or termination of such reduction or elimination and the increase in imports shall not by itself preclude the determination under sub-rule (3).

8. Preliminary findings. -

- (1) The Director-General shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, he may record a preliminary finding regarding serious injury or threat of serious injury.
- (2) The Director-General shall issue a public notice regarding his preliminary findings.
- (3) The Director-General shall send a copy of the public notice to the Central Government in the Ministry of Commerce and in the Ministry of Finance.

9. Application of provisional safeguard measure. -

If the Director-General determines in his preliminary findings that as a result of reduction or elimination of a custom duty under the Trade Agreement, an originating article of the Republic of Singapore is being imported in such increased quantity in absolute terms and other such conditions that the imports of such article from the Republic of Singapore alone constitutes a substantial cause of serious injury or threat of serious injury to domestic industry, the Central Government may -

- (i) suspend further reduction of any rate of customs duty on the article provided for under the Trade Agreement; or
- (ii) increase the rate of customs duty on the article to a level not to exceed the lesser of, -
- (a) the Most Favoured Nation (MFN) applied rate of customs duty on the article in effect at the time the measure is taken, and,
- (b) the Most Favoured Nation (MFN) applied rate of customs duty on the article in effect on the day immediately preceding the date of start of the period of investigation; or
- (iii) in a case of customs duty being applied to an article on seasonal basis, increase the rate of custom duty to a level not to exceed the lesser of the Most Favoured Nation (MFN) applied rate of customs duty that was in effect on the article for the corresponding season immediately preceding the date of investigation:

Provided that such safeguard measure shall remain in force only for a period not exceeding two hundred days from the date on which it was imposed.

10. Final findings.

- (1) The Director-General shall, within eight months from the date of initiation of the investigation extendable by the Central Government to maximum of one year, determine whether, -
- (i) the increased imports of the article under investigation has caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry; and
- (ii) a causal link exists between the increased imports due to preferential treatment under the Trade Agreement and serious injury or threat of serious injury.

- (2) The Director-General shall also give his recommendation regarding safeguard measures which, if applied, would be adequate to prevent or remedy serious injury and to facilitate positive adjustment.
- (3) The Director-General shall also make his recommendations regarding the duration of the safeguard measure:

Provided that where the period recommended is more than one year, the Director-General shall also recommend progressive liberalisation adequate to facilitate positive adjustment.

- (4) The final findings, if affirmative, shall contain all information on the matter of facts and law and reasons which have led to the conclusion.
- (5) The Director-General shall issue a public notice recording his final findings.
- (6) The Director-General shall send a copy of the public notice regarding his final findings to the Central Government in the Ministry of Commerce and in the Ministry of Finance.

11. Application of safeguard measures.

On receipt of the recommendation of the Director-General, the Central Government may suitably amend the notification, issued under sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 to give effect to the provisions of the Trade Agreement, in respect of the product covered under the final findings, in order to prevent or remedy serious injury and to facilitate positive adjustment:

Provided that no safeguard measure shall be taken against any particular article while a global safeguard measure in respect of that article is in place. In the event of a global safeguard measure being taken in respect of a particular article, any existing bilateral safeguard which is taken against that article shall be terminated and upon termination of the safeguard measure, the rate of duty shall be the rate which would have been in effect but for the action.

12. Date of commencement of safeguard measures.

The safeguard measure taken under rule 11 shall take effect from the date of publication of the notification, in the Official Gazette whereby such measure is taken.

13. Refund of duty.

If the safeguard measure taken after the conclusion of the investigation results in a level of exemption which is lower than that already given as provisional safeguard measure, the differential duty shall be refunded to the importer.

14. Duration.

- (1) The safeguard measure applied under rule 12 shall be only for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate positive adjustment.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) of this rule, the safeguard measure applied under rule 12 shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of two years from the date of its imposition:

Provided that if the Central Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition by one year.

- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) of this rule, the safeguard measure taken under rule 12 shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of three years from the date of its imposition.

15. Review.

- (1) Director-General shall, from time to time, review the need for continued application of the safeguard measure and shall, if he is satisfied on the basis of information received by him that -

- (i) safeguard measure is necessary to prevent or remedy serious injury and there is evidence that the industry is adjusting positively, he may recommend to the Central Government for the continued imposition of duty;
- (ii) there is no justification for the continued imposition of such measure, recommend to the Central Government for its withdrawal:

Provided that where the period of application of safeguard measure exceeds one year the Director-General shall review the situation not later than the mid-term of such imposition, and, if appropriate, recommend for withdrawal of such safeguard measure or for suitable modification of the same.

- (2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding eight months from the date of initiation of such review or within such extended period as the Central Government may allow.
- (3) The provisions of rules 4, 5, 6 and 10 shall, *mutatis mutandis* apply in the case of review.

[F. No. 467/06/2008-Cus.-V]

SATISH KUMAR REDDY, Director